that the price marked on some of the pre-packed commodities is higher than the actual selling price. The declared sale price on a pre-package includes various pricing components like taxes, freight, commissions, etc. The price printed is only the maximum price and the actual selling price may be lower than the marked price depending up on these factors.

(b) to (d) The Ministry has constituted an Expert Committee comprising of representatives of Trade and Industry, Voluntary Consumer Organisations and Government bodies to review and suggest the best method of marking the retail sale price on pre-packed commodities which could be incorporated, if feasible, in the Standards of weights and Measures (Packaged Commodities) Rules.

(e) and (f) In its first meeting, the Expert Committee viewed that the manufacturers may be asked to print the 'ex-factory price' on all pre-packed commodities in addition to the Maximum Retail Sale Price. However, the representatives of Trade and Industry Associations have expressed their difficulties in the implementation of this proposition.

Unemployment in the country

277. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :
DR. MURLI MANOHAR JOSHI :

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) what is the number of unemployed persons in the country during the years 1991, 1992, 1993 and 1994, together with the break-up in terms of rural urban and male and female ;

(b) what is the actual number of jobs created and the target fixed in the Eighth Plan in Government and private sectors ;

(c) what is the rate of growth of employment during the above period; and

(d) what will be the backlog of unemployment as on March, 1995 ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANGO) : (a) The estimated unemployment in the country as at the end of March of each year for 1991 to 1994 is given below :—

Year (at the end of March)	Unemployment (millions)
1991	13.4
1992	17.0
1993	17.3
1994	18.5

Break-up according to rural and urban male and female is not available.

(b) The Eighth Plan (1992-97) envisaged creation of 43 million additional employment opportunities during the Plan period. It has been estimated that 6.4 million employment opportunities were created during 1992-93 and 5.6 million during 1993-94. According to the Quick Estimates available. Public sector employment increased by 0.18 million during 1992-93 but declined by 0.51 million during 1993-94.

(c) Employment is estimated to have grown by 2.1 per cent during 1992-93 and 1.8 per cent during 1993-94.

(d) Backlog of unemployment in March 1995 would depend, *inter alia*, on the extent of employment generation that would take place during 1994-95.

गरीबी उन्मूलन

*78. **श्री इकबाल सिंह :**

श्री ईश दत्त यादव

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गरीबी के उन्मूलन और अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) गरीबी उन्मूलन भारत में नियोजित विकास का एक प्राथमिक उद्देश्य रहा है। ग्रामीण गरीबी की समस्या पर छठी योजना के दौरान अधिक ध्यान दिया गया था। यह महसूस किया गया कि गरीबी उन्मूलन की सतत कार्यनीति विकास की अपनी प्रक्रिया में ही उत्पादक रोजगार अवसरों को बढ़ाने पर आधारित होनी चाहिए।

बहरहाल, थोड़े समय में, जहां तक विकास प्रक्रिया समाज के कुछ तबकों तक नहीं पहुंचेगी, अतः सीधे राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से गरीबों को अनुपूरक रोजगार तथा आय प्रदान करना आवश्यक है। गरीबी उन्मूलन के लिए चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमें ये हैं। (i) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)**, (ii) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), (iii) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) तथा (iv) नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.] आठवीं योजना के ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम व्यापक आधार पर जारी रहेंगे।

(I) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)**

आई.आर.डी.पी. एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अभिनिर्धारित ग्रामीण परिवारों को दीर्घविधिक आधार पर गरीबी रेखा को पार करने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों एवं उपयुक्त कौशल प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए सब्सिडी तथा बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। सब्सिडी पर होने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 आधार पर बांटा जाता है। लक्ष्य वर्ग में अधिकांशत : छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण कारीगर है। अब तक 42 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की गई है।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसैम) आई.आर.डी.पी. का एक सहायक घटक है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोगजार कार्यक्रम शुरू करने के लिए तकनीकी तथा मूलभूत उद्यमी कौशल प्रदान किया जाता है, अभी हाल ही में ट्राइसैम प्रशिक्षु मजदूरी रोजगार शुरू कर सकते हैं। प्रति वर्ष 2–3 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (डी.डब्लू.सी.आर.ए.) भी आई.आर.डी.पी. की एक उप स्कीम है, जिसम ग्रामीण परिवारों की महिला सदस्यों पर ध्यान दिया जाता है। इन महिलाओं की आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए सज्जित करने के उद्देश्य से 10–15 के दलों म संगठित किया जाता है। गरीब महिलाओं की रोजगार, कौशल निर्माण, प्रशिक्षण, ऋण तथा सहायक सेवाओं तक पहुंच को सुधारने के अतिरिक्त यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा तथा शिशु देखभाल जैसी अन्य सेवाओं की तरह लक्ष्य दल की ओर